भारत का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2073] No. 2073] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2011/कार्तिक 11, 1933

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2011/KARTIKA 11, 1933

जल संसाधन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2011

का.आ. 2482(अ).—अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं. का.आ. 437(अ) द्वारा तारीख 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन अन्तर्राज्यिक कावेरी नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

उक्त अधिकरण से उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन उसकी रिपोर्ट और विनिश्चय को 5 अगस्त, 2005 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी;

केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 980(अ), तारीख 12 जुलाई, 2005 द्वारा, रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अविध को 6 अगस्त, 2005 से एक वर्ष की और अविध के लिए विस्तारित किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 1399(अ), तारीख 1 सितम्बर, 2006 द्वारा, रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अविध को 6 अगस्त, 2006 से छह मास की और अविध के लिए फिर विस्तारित किया था;

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन उसकी रिपोर्ट और विनिश्चय, 5 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत कर दिए थे;

और पक्षकार राज्यों और केन्द्रीय सरकार, ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के परंतुक के अधीन 27 अप्रैल, 2007, 30 अप्रैल, 2007 और 3 मई, 2007 को उक्त अधिकरण को और निर्देश किया था तथा अधिकरण ने 3 मई, 2007 से एक वर्ष के भीतर अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिकरण के अनुरोध पर अधिसूचना सं. का.आ. 1164(अ), तारीख 16 मई, 2008 द्वारा उक्त अधिकरण द्वारा और रिपोर्ट को प्रसूत करने की अविध को 3 मई, 2008 से छह मास की अतिरिक्त अविध के लिए विस्तारित किया था; तथा अधिसूचना सं. का.आ. 2506(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2008 द्वारा उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अविध को 3 नवम्बर, 2008 से एक वर्ष की और अविध के लिए विस्तारित किया था; तथा अधिसूचना सं. का.आ. 2628(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 2009 द्वारा उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अविध को 3 नवम्बर, 2009 से एक वर्ष को और अविध के लिए विस्तारित किया था तथा पुनः अधिसूचना सं. का.आ. 2605(अ), तारीख 21 अक्तूबर, 2010 द्वारा उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अविध को 3 नवम्बर, 2010 द्वारा उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अविध को 3 नवम्बर, 2010 से एक वर्ष की और अविध के लिए विस्तारित किया था;

और उक्त अधिकरण ने अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को विस्तारित करने का पुन: अनुरोध किया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अविध को 3 नवम्बर, 2011 से एक वर्ष की और अविध के लिए विस्तारित करती है।

[फा. सं. 1/1/2005-बीएम] ध्रुव विजय सिंह, सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2011

S.O. 2482(E).—Whereas, the Cauvery Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to the said Tribunal) was constituted on 2nd June, 1990 vide notification number S.O. 437(E), dated the 2nd June, 1990 under Section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State River Cauvery and river valley thereof;

And whereas the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of the said Act on or before 5th August, 2005;

And whereas the Central Government, vide notification number S.O. 980(E), dated the 12th July, 2005 had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 6th August, 2005;

And whereas the Central Government vide notification number S.O. 1399(E), dated the 1st September, 2006 extended the period of submission of report and decision for a further period of six months with effect from 6th August, 2006;

And whereas the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of the said Act on 5th February, 2007;

And whereas the party States and Central Government made further reference to the said Tribunal

under the proviso to sub-section (3) of Section 5 of the said Act on 27th April, 2007, 30th April, 2007 and 3rd May, 2007 and the Tribunal had to submit a further report within one year from 3rd May, 2007;

And whereas the Central Government, on request of the said Tribunal, vide notification number S.O. 1164(E), dated 16th May, 2008 extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of six month with effect from 3rd May, 2008; and vide notification number S.O.2506(E), dated 23rd October, 2008 extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from 3rd November, 2008 and again vide number S. O. 2628(E), dated the 19th October, 2009 extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from 3rd November, 2009; and again vide notification number S.O. 2605(E), dated 21st October, 2010 extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from 3rd November, 2010;

And, whereas the said Tribunal has again requested to extend the period of submission of further report;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (3) of Section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from 3rd November, 2011.

[F. No. 1/1/2005-BM] DHRUV VIJAI SINGH, Secy.